The Chinese Foreign Minister and a senior Chinese leader are also expected to visit India.

Meanwhile, India-China relations in various fields such as trade and economic cooperation, cultural exchanges, science and technology, agricultural cooperation and party to party relations, continue to be consolidated and strengthened.

While overall exchanges with Chint show a steady improvement, Government have continued to address outstanding issues with China, including the complicated boundary question. The Joint Working Group on the boundary question has held five meetings so far and has made steady progress in its discussions aimed at reducing our differences on the boundary question in order to arrive at a fair, reasonable and mutually acceptable settlement. The Joint Working Group is also seeking ways to establish measures to ensure maintenance of peace and tranquility all along the Line of Actual Control. The next meeting of the Joint Working Group will be held in New Delhi towards the end of June, 1993.

Government in sincerely committed to further developing friendly, mutually benefical and good neighbourly relations with China.

इस्लामी देशों के संगठन के सम्मेलन में भारत के विरूद्ध किये गये उल्लेख

*226. **श्री नौनिहाल सिंह :**
श्री शांति त्यागी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान में हुये इस्लामी देशों के संगठन के सम्मेलन में भारत के विरूद्ध प्रस्तावित प्रतिबंधों और निन्दात्मक कार्यवाही का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार अन्तराष्ट्रीय स्तर पर इस्लामी देशों के भारत-विरोधी रवैये से निपटने के लिये क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकारी प्रवक्ता के वक्तव्य का पाठ विवरण के रूप में संलग्न है **(नीचे देखिये)** जिसमें भारत सरकार की प्रतिक्रिया बताई गई है। सरकार पाकिस्तान की ओर से किये जाने वाले भारत विरोधी प्रचार का प्रतिकार किये जाने की आवश्यकता के प्रति सचेत है। हमने सभी मित्र देशों के समक्ष मसलों को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिये कदम उठाये हैं जिनमें इस्लामी देशों के संगठन के सदस्य भी शामिल है।

विवरण

इस्लामी देशों के संगठन के विदेश मंत्रियों की कराची में आयोजित 21वीं बैठक समाप्ति पर कश्मीर तथा भारतीय मुसलमानों के हितों के संबंध में इस्लामी देशों संगठन के संकल्पों पर सरकारी प्रवक्ता का वक्तव्य

इस्लामी देशों के संगठन के विदेश मंत्रियों की कराची में 29 अप्रैल, 1993 को आयोजित 21वीं बठक में पारित विज्ञप्ति एवं संकल्पों से संबंधित खबरें सरकार ने अखबारों में देखी हैं।

कराची में पारित विज्ञप्ति एवं संकल्पों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ओआईसी विदेश मंत्रियों की बैठक को ओआईसी सचिवालय तथा मेजबान देश के कुछ तत्वों ने गलत ढंग से समझाया है। ऐसी परिस्थितियों में विज्ञप्ति तथा

संकल्पों में अभिव्यक्त विचारों से भारत सरकार को आश्चर्य नहीं हुआ है। साथ ही, भारत सरकार ओ.आई.सी. के विदेश मंत्रियों की कराची में हुई बैठक में किये गये मूल्यांकनों तथा सिफारिशों पर अपनी स्पष्ट आपत्ति व्यक्त करती है। हम उन्हें पूर्णतः अस्वीकार करते हैं।

कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है इसमें तय होने की बात सिर्फ यह है कि पाकिस्तान सत्य को स्वीकार करे तथा इस उप महाद्वीप में शांति एवं स्थायित्व के व्यापक उद्देश्यों के लिये भारत के साथ सहयोग करे। ओआईसी के संकल्प से पाकिस्तान को इस बात का प्रोत्साहन मिलने के अतिरिक्त और कोई दूसरा प्रयोजन पूरा नहीं होगा कि वह भारत के खिलाफ आतंकवाद एवं विध्वंश को निरन्तर अपना समर्थन देता रहे और यह काम करवाता रहे।

ओआईसी ने यह भी मान लिया है कि भारत में रहने वाले 10 करोड़ मुसलमान भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। यह बड़ी अजीब बात है कि एक ऐसे संगठन ने जो यह बात मानने के लिये तो तैयार नहीं है कि संसार के मुस्लिम आबादी वाले सबसे बड़े राज्यों में एक यानि भारत को उसके कार्यकलापों में हिस्सा लेने दिया जाय, अब इस बात का दम भर रहा है कि वह इन मुसलमानों के हितों की रक्षा करेगा। इस निरर्थक कार्य में निहित राजनैतिक चालबाजी बहुत साफ है। भारतीय उप-महाद्वीप में अल्पसंख्यकों की स्थिरता एवं संरक्षण को इस्लामी देशों संगठन के ऐसे पक्षपातपूर्ण वक्तव्यों से कोई सहायता नहीं मिलेगी।

30 अप्रैल, 1993

नई दिल्ली

Action against Officials Responsible for withdrawal of SPG cover to late Shri Rajiv Gandhi

*227. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Verma Commission has stated in its report that withdrawal of the SPG cover had led to the assassination of late Shri Rajiv Gandhi;

(b) if so, the steps taken by Government to fix the responsibility and bring to book the officials responsible; and

(c) whether any criminal action has been taken against those found responsible for this lapse, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): (a) to (c) The Verma Commission of Inquiry has held that the proximate cause of the assassination of Shri Rajiv Gandhi was the failure on the part of the Tamil Nadu Police to implement the prescribed security guidelines strictly, particularly in regard to access control in the proximity of Shri Rajiv Ganhi which enabled the human bomb to gain access near the VIP, leading to his assassination. The Commission has also held that the Central Government failed to provide effective alernative proximate security cover for Shri Rajiv Gandhi after the withdrawal of SPG cover, which was not justified. This has been held to be a contributory lapse of the Central Government.

The Commission has not named any individual officers of the Central Government as being responsible for the above stated contributory lapse.

A copy of the Report of the Commission has been forwarded to the State Government of Tamil Nadu. The State Government has been